

and Government should allow full rebate in excise duty and allow the converted sugar for free sale to recoup the extra expense incurred in this process; and

7. Purchase of jaggery by distilleries for conversion into alcohol and of alcohol made directly from jaggery.

I am sure the Minister for Agriculture who is himself a practising farmer would appreciate the serious crisis facing the industry and take all suitable steps to alleviate the difficulties of the jaggery producers.

(iv) STEPS TO CHECK POLLUTION OF THE WATER OF GANGA AND YAMUNA RIVERS

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, गंगा एवं यमुना नदियां भारत की नहीं वरन् संसार की प्रसिद्ध नदियों में से हैं। ये नदियां उत्तरी भारत के जन जीवन का स्रोत रहीं हैं, परन्तु यह दुखद सत्य है कि आज गंगा एवं यमुना का पानी सब से अधिक प्रदूषित है। स्थान-स्थान पर यह मानव-उपयोग के उपयुक्त नहीं है। सेन्ट्रल बोर्ड आफ प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल आफ वाटर पोल्यूशन ने अपनी रपट में स्वीकार किया है कि गंगा के जल-प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा घुलनशील आक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से पानी अस्वास्थ्यकर हो गया है। गंगा, कन्नोज, कानपुर, वाराणसी, मोकामा, बरौनी में अधिक प्रदूषित है। 1979 से गंगा के पानी की जांच कर के सेन्ट्रल बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि गंगा का पानी इन स्थानों पर मानव-उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हुगली में मछली की मात्रा हाल के वर्षों में लगभग 80 प्रतिशत रह गई है। पानी की स्वतः शुद्धीकरण की प्रक्रिया अब क्षीण हो रही है और तात्कालीन मानव

हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 48 प्रथम वर्ग के नगरों एवं 66 द्वितीय वर्ग के नगरों का गंदा पानी तथा सैकड़ों प्रमुख उद्योगों का उच्छिष्ट पदार्थ गंगा के जल को प्रतिक्षण प्रदूषित कर रहे हैं। कानपुर में ही 18 प्रतिशत प्रदूषण मात्र उद्योगों से है। तट पर बसे नगरों से गन्दे नालों का अविरल प्रवाह तथा प्रतिदिन हजारों बिना जली एवं अर्धजली लाशों का प्रवाह स्थिति को और अधिक भयावह बना रहे हैं। डिपार्टमेंट आफ सिविल इंजीनियरिंग रूड़की यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन के पश्चात् घोषित किया है कि यमुना नदी "रूग्ण" है। इसका पानी दिल्ली, मथुरा तथा आगरा में जन-उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इस में उद्योगों द्वारा त्यक्त सामग्रों बड़े पैमाने पर पानी को प्रदूषित कर रही है। साथ ही नगरों के गन्दे नाले जल प्रदूषण की वृद्धि में चिन्ता-जनक योगदान दे रहे हैं। यहां तक कि लन्दन के पब्लिक हेल्थ वाटर वर्क्स डायरेक्टर के डा० टेलर ने सलाह दी है कि यमुना के पानी के प्रदूषण को दृष्टिकोण रखते हुए ओखला जल संयंत्र कप त्याग दिया जाना चाहिए। माननीय निर्माण एवं आवास मंत्री जी ने भी गत 30 नवम्बर, को सदन में स्वीकार किया था कि यमुना का पानी दिल्ली एवं इटावा के बीच पीने योग्य नहीं रह गया है।

मैं एतद् द्वारा सरकार का ध्यान गंगा एवं यमुना नदियों के पानी के प्रदूषण की भयावह स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इसे गंभीरता से ले तथा इस दिशा में शीघ्र प्रभावकारी कदम उठाये। उद्योग अपने द्वारा उच्छिष्ट पदार्थों के शुद्धीकरण की कोई व्यवस्था करें। स्थापना के समय ही उद्योगों को

[श्री बी० डी० सिंह]

प्रदूषण-नियंत्रण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। नियंत्रण-व्यय उद्योगों की स्थापना-व्यय का अंश स्वरूप होना चाहिए, जसा कि अन्य अनेक देशों में होता है। नगरों के गंदे पानी के शुद्धिकरण की अनिवार्य रूपा से व्यवस्था की जानी चाहिए। नदियों का शुद्ध जल गंदे पानी में मिला कर सिंचाई की जा सकती है। नदियों के तट पर बसे नगरों में विद्युत-शवदाह-गृहों की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य व्यापार निगम को देखना चाहिए कि चीनी मिलों द्वारा मोलेसेस का भण्डारण समुचित ढंग से किया जाता है तथा वह गन्तव्य स्थान को समय पर चला जाता है। इस प्रकार गंगा तथा यमुना के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय शीघ्र तथा प्रभावकारी ढंग से करें।

(v) NEED TO CONSIDER THE WEST BENGAL GOVERNMENT'S PROPOSAL FOR SETTING UP OF PRODUCTION UNIT OF SYNTHETIC CRUDE FROM COAL

SHRI SUBODH SEN (Jalpaiguri): Mr. Speaker, Sir, the West Bengal Government has proposed to the Centre a Rs. 1850 crores integrated project for the production of synthetic crude is the Raniganj-Andal-Durgapur coal belt for phase-wise implementation. The synthetic crude would serve as a partial substitute for imported petrol, diesel and kerosene and other fuels and chemicals from coal. The integrated project will create additional employment for one lakh or more people. The West Bengal Government's Proposal envisaged four phases. Under phase I, production of industrial gases from coal to meet the requirement of fuel demands of major industries in the Durgapur-Asansol-belt such as Durgapur Steel Plant, Alloy Steel Plant, Indian Iron and Steel Company and in and around Calcutta for decentralised industries was proposed.

Phase II production of methanol from coal as a blend item will save quantitatively the use of crude being so employed for the manufacture of various petroleum products and as raw material for many downstream chemical industries in the Eastern Region.

In Phase III, production of synthetic oil from coal, with particular emphasis on production of diesel, kerosene along with associated higher alcohol and chemicals which will be utilised for many downstream industries in the State and elsewhere. The IVth and final phase envisaged the production of ammonia from coal for nitrogenous fertiliser and manufacture of nitric acid, ammonia nitrate and nitrous oxide. The integrated project would mean production of synthetic crude one million tonnes a year, 500000 tonnes of methanol per annum and 50 million cubic feet a day of industrial gases. Coal consumption at the stage of synthetic crude production will be around 7.44 million tonnes a year cumulative and inclusive of combined cycle power generation of 110 MW to meet in-plant requirements. A recent report on coal samples tested abroad categorically indicated that the Raniganj non-coking coal was the most suitable raw material for pressure gasification. A suitable pressure gasification process could be very effectively adopted for production of synthetic crude Methanol and industrial gases including combined cycle power generation from coal.

Under the circumstances, I urge upon the Government to consider immediately the West Bengal Government's proposal for setting up this project for production of synthetic crude from coal.

(vi) REPORTED DISAPPEARANCE OF YASWANT FORT AT KAGAL IN MAHARASHTRA

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central): Mr. Speaker, Sir, late Lord Curzon who initiated legislation governing the An-